गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर): (क) और (ख) इस संबंध में 27 जून, 1983 के "नव भारत टाइम्स" में एक समाचार प्रकाशित हुआ था।

रेल सुधार समिति ने निम्नलिखित सिफारिशें कीं :—

(1) रेल समिति का छुटपुट चोरी के अलावा रेलों में अपराधों से संबंधित संसद प्रश्नों का उत्तर देने का उत्तरदायित्व गृह मंत्रालय का होना चाहिए।

(2) रेल सम्पत्ति को छुटपुट चोरी से संबंधित प्रश्नों का उत्तर रेलवे द्वारा दिया जाना चाहिए।

सरकार द्वारा उपयुक्त सिफारिशें मान ली गई हैं।

Employment of Ex-Convicts in Government Services

1235. SHRI AMARPROSAD CHAKRABORTY: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news item which appeared in the *Statesman* of 10th April, 1983 under the Caption The State should employ-ex. convicts, says report"; and

(b) if so, the steps proposed to be taken by Government to employ the ex-convicts in Government services?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI NIHAR RANJAN LASKAR): (a) Yes, Sir.

(b) The Central Government had issued instructions earlier to all States and UTs for considering the desirability of taking suitable steps to ensure that ex-convicts do not suffer any disabilities for rehabilitation in society and can find employment with Government on their merits on release from jails.

The Jail Reforms Committee set up by the Government of India has also made certain recommendations on this subject which would be processed in consultation with the State Governments and further appropriate measures will be taken.

Recession in Ancillary Units

1236. SHRI AMARPROSAD CHAKRABORTY: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to reports appearing in a section of the Press regarding "recession in ancillary Units";

(b) if so, the names of the ancillary units which have been so hit by recession; and

(c) what steps Government have taken to boost these ancillary units?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) to (c) The news-item relates to Study undertaken by the Economic and Scientific Research Foundation, New Delhi on the Parent-Ancillary production link in the tractor industry. The Study does not indicate the names of ancillary units reportedly hit by recession. There has since been increase in production and sales of tractors, which will benefit the ancillary units also.

Levy Cement to Orissa

1237. SHRI GAYA CHAND BHUYAN: Will the Miniser of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the State Government of Orissa urged the Central Government for the release of 1,50,000 M. Ts. levy cement besides the normal allotment for the restoration of buildings, culverts and bridges damaged during the last year due to unprecedented flood; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI NARAYAN DATT TIWARI): (a) and (b) The State Government of

Orissa had in November, 1982, requested for additional ad-hoc allocation of 1.8 lakh tonnes of levy cement for flood relief works in the State. The State Government of Orissa was advised that the requirement of levy cement may be met from the additional ad-hoc allocation of 50,000 tonnes of levy cement made in favour of the State Govt. for cyclone relief works during quarter II and III 1982, part of which had remained unlifed and also from the regular quarterly allocation made to the State of Orissa.

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

1238. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या क्या है और उनमें से कितने सदस्य हिन्दी बोल, लिख और पढ़ सकते हैं तथा वे सदस्य कितने हैं जो हिन्दी केवल बोल सकते हैं परन्तु उसे लिख और पढ़ नहीं सकते हैं और वे सदस्य कौन-कौन से हैं जो हिन्दी न तो लिख सकते हैं और न ही बोल सकते हैं ;

(ख) क्या समिति ने इस वर्ष के दौरान परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन छोटे बड़े सभी विभागों तथा अधीनस्थ संस्थाओं का निरीक्षण कर लिया है और उनके बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है अथवा क्या सभी कार्यालयों का निरीक्षण करना संभव नहीं है ;

(ग) इस वर्ष के दौरान समिति की गतिविधियों का ब्योरा क्या है ; और

(घ) इस समिति ने अनुपात के अनुसार अधिकतम हिन्दी कर्मचारियों को नियुक्त करने और विभागीय पुस्तकालय में हिन्दी पुस्तकें तथा हिन्दी के संदर्भ ग्रंथ रखने और पत्र पत्रिकाओं का समय पर प्रकाशन करने के लिए क्या उपाय किये हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी , परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, इलक्ट्रानिकी तथा महासागर विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल): (क) परमाणु ऊर्जा विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति में 14 सदस्य हैं, जिनमें से 12 इस विभाग के अधिकारी हैं तथा अन्य 2 में से एक तो राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि हैं और दूसरे हिन्दी शिक्षण योजना के । सभी 14 सदस्य हिन्दी बोल, लिख और पढ़ सकते हैं ।

(ख) भारत सरकार द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन समिति के लिए जो कार्य सामान्य रूप से निर्धारित किए गए हैं उनमें कार्यालयों का निरीक्षण करना शामिल नहीं है । इस कारण से समिति ने स्वयं किसी कार्यालय का निरीक्षण नहीं किया है । तथापि, जब भी विभाग के किसी अधिकारी ने किसी कार्यालय का निरीक्षण हिन्दी के प्रयोग की स्थिति के अध्ययन के लिए किया है जब उस निरीक्षण की रिपोर्ट समिति को भी प्रस्तुत की गई है ।

(ग) इस विभाग की राजभाषा कार्यान्वयन समिति सामान्य रूप से काम करती है । सरकारी पत्राचार में हिन्दी के प्रयोग की समीक्षा करने के उद्देश्य से उसकी आवधिक बैठकें होती हैं । यह समिति परमाणु ऊर्जा विभाग में राजभाषा के कार्यान्वयन के काम को देखती है और इस विभाग के संघटक यूनिटों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के काम का पर्यवेक्षण करती है ।

(घ) विभाग में हिन्दी स्टाफ संबंधी आवश्यकता की समीक्षा वास्तविक कार्यभार को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर